

एफ आर बी एम अधिनियम के घोषित उद्देश्यों में से एक यह है कि केंद्र सरकार एक मध्यम-अवधि के ढांचे में अपनी राजकोषीय नीति का संचालन करेगी। इसे प्राप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 3 में, सरकार द्वारा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) विवरण, राजकोषीय नीति योजना (एफ पी एस) विवरण और वृहत आर्थिक रूपरेखा (एम एफ) विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदान की मांगों के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 2012 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन द्वारा, एक मध्यम अवधि के व्यय ढांचे (एम टी ई एफ) विवरण को भी संसद में प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

अप्रैल 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम के संशोधन के बाद, अलग-अलग विवरणियों के स्थान पर एक मध्यम अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति योजना (एम टी एफ पी सह एफ पी एस) का विवरण प्रस्तुत किया गया। वृहत आर्थिक रूपरेखा (एम ई एफ) और मध्यम अवधि व्यय ढांचा (एम टी ई एफ) विवरणियों को पहले की तरह संसद में प्रस्तुत किया जाना था। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि एम टी एफ पी सह एफ पी एस में सकल घरेलू उत्पाद(जी डी पी) के प्रतिशत के रूप में एफ डी, आर डी, प्राथमिक घाटा, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केंद्र सरकार ऋण के संबंध में तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे। एम टी एफ पी सह एफ बी एस विवरण में राजकोषीय दृष्टिकोण, जी डी पी वृद्धि अनुमानों प्राप्तियां व व्यय के अनुमानों से संबंधित अंतर्निहित धारणाओं को प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। एम टी ई एफ विवरण, सभी निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्यों के साथ अंतर्निहित धारणाओं और जोखिमों के ब्यौरे को शामिल करता है।

यह अध्याय 2017-18 एवं 2018-19 के लिए संघ सरकार की वास्तविक प्राप्तियों और व्ययों का राजकोषीय नीति विवरणी और बजट सार में किए गए अनुमानों के बीच भिन्नता का विश्लेषण करता है।

तालिका 4.1 में वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एम टी एफ पी सह एफ पी एस; एम टी ई एफ; बजट और संशोधित अनुमानों और दोनों वर्षों के लिए वास्तविक राशियों की तुलना दर्शायी गई है।

तालिका 4.1: एम टी एफ पी/ एम टी ई एफ विवरणियाँ और बजट दस्तावेजों में 2017-18 व 2018-19 के लिए अनुमान

2017-18 के लिए आंकलन/अनुमान/वास्तविक (जी डी पी प्रतिशतता के रूप में)

	2015-16 एम टी एफ पी में चित्रण	2016-17 एम टी एफ पी में चित्रण	2017-18 के लिए बजट अनुमान	2017-18 के लिए संशोधित अनुमान	2017-18 के लिए वास्तविक
राजकोषीय संकेतक	फरवरी 2015	फरवरी 2016	फरवरी 2017	फरवरी 2018	फरवरी 2019
राजकोषीय घाटा	3	3	3.2	3.5	3.5
राजस्व घाटा	2	1.8	1.9	2.6	2.6
प्रभावी राजस्व घाटा	0	0.6	0.7	1.5	1.5
कुल बकाया देयताएं	42.8	46.8	44.7	50.1	44.8
सकल कर राजस्व	10.7	10.9	11.3	11.6	11.2

2017-18 के लिए आंकलन/अनुमान/वास्तविक (₹ करोड़ में)

	2015-16 एम टी एफ पी में चित्रण	2016-17 एम टी एफ पी में चित्रण	2017-18 के लिए बजट अनुमान	2017-18 के लिए संशोधित अनुमान	2017-18 के लिए वास्तविक
प्राप्तियां	फरवरी-2015	फरवरी-2016	फरवरी-2017	फरवरी-2018	फरवरी 2019
कर राजस्व	12,09,937	11,97,970	12,27,014	12,69,454	12,42,488
गैर कर राजस्व	2,49,104	3,37,456	2,88,757	2,35,974	1,92,745
राजस्व प्राप्तियां (ए)	14,59,041	15,35,426	15,15,771	15,05,428	14,35,223
पूंजीगत प्राप्तियां जिनमें से:					
i) ऋण और अग्रिमों की वसूली	10,500	10,500	11,932	17,473	15,633
ii) अन्य गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	50,000	40,000	72,500	1,00,000	1,00,045
गैर-ऋण प्राप्तियां {(ए)+(i)+(ii)} (बी)		15,85,926	16,00,203	16,22,901	15,50,911
iii) उधार-सार्वजनिक ऋण व अन्य देनदारियां	5,44,614	5,12,257	5,46,532	5,94,849	5,91,062
	एम टी ई एफ 2015-16	एम टी ई एफ 2016-17	बजट अनुमान 2017-18	संशोधित अनुमान 2017-18	वास्तविक 2017-18
व्यय/घाटा	अगस्त-2015	अगस्त-2016	फरवरी-2017	फरवरी-2018	फरवरी-2019
राजस्व व्यय (सी)	17,79,614	18,29,317	18,36,934	19,44,305	18,78,833
पूंजीगत व्यय	2,84,541	2,68,866	3,09,801	2,73,445	2,63,140
कुल व्यय (डी)	20,64,155	20,98,183	21,46,735	22,17,750	21,41,973
राजकोषीय घाटा (बी-डी)	(-5,44,614)	(-5,12,257)	(-5,46,532)	(-5,94,849)	(-5,91,062)
राजस्व घाटा (ए-सी)	(-3,20,573)	(-2,93,891)	(-3,21,163)	(-4,38,877)	(-4,43,600)

पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	3,16,754	2,00,000	1,95,350	1,89,245	1,91,034
प्रभावी राजस्व घाटा (ई आर डी)	(-3,819)	(-93,891)	(-1,25,813)	(-2,49,632)	(-2,52,566)
जी डी पी	1,77,93,186	1,68,72,811	1,68,47,455	1,67,84,679	1,70,98,304

2018-19 के लिए आंकलन/अनुमान/वास्तविक

(जी डी पी प्रतिशतता के रूप में)

	2015-16 एम टी एफ पी में चित्रण	2016-17 एम टी एफ पी में चित्रण	2017-18 के लिए बजट अनुमान	2017-18 के लिए संशोधित अनुमान	2017-18 के लिए वास्तविक
राजकोषीय संकेतक	फरवरी-2016	फरवरी-2017	फरवरी-2018	फरवरी 2019	फरवरी-2020
राजकोषीय घाटा	3	3	3.3	3.4	3.4
राजस्व घाटा	1.3	1.6	2.2	2.2	2.4
प्रभावी राजस्व घाटा	0	0.4	1.2	1.1	1.4
कुल बकाया देयताएं	44.4	42.8	48.8	-	-
केन्द्र सरकार के ऋण				48.4	48.7
सकल कर राजस्व	11.1	11.6	12.1	11.9	11

2018-19 के लिए आंकलन/अनुमान/वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	एम टी एफ पी 2016-17 में चित्रण	एम टी एफ पी 2017-18 में चित्रण	2018-19 के लिए बजट अनुमान	2018-19 के लिए संशोधित अनुमान	2018-19 के लिए वास्तविक
प्राप्तियां	फरवरी-2016	फरवरी-2017	फरवरी-2018	फरवरी 2019	फरवरी-2020
कर राजस्व	13,72,772	14,15,186	14,80,649	14,84,406	13,17,211
गैर कर राजस्व	3,43,193	2,64,168	2,45,089	2,45,276	2,35,705
राजस्व प्राप्तियां (ए)	17,15,965	16,79,354	17,25,738	17,29,682	15,52,916
पूँजीगत प्राप्तियां जिनमें से:	6,18,258	6,60,651	7,16,475	7,27,553	7,62,197
i) ऋण और अग्रिमों की वसूली	10,500	10,000	12,199	13,155	18,052
ii) अन्य गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां	40,000	47,000	80,000	80,000	94,727
गैर-ऋण प्राप्तियां {(ए)+(i)+(ii)}(बी)	17,66,465	17,36,354	18,17,937	18,22,837	16,65,695
iii) उधार-सार्वजनिक ऋण व अन्य देनदारियां	5,67,758	6,03,651	6,24,276	6,34,398	6,49,418

	एम टी एफ पी 2016-17 में चित्रण	एम टी एफ पी 2017-18 में चित्रण	2018-19 के लिए बजट अनुमान	2018-19 के लिए संशोधित अनुमान	2018-19 के लिए वास्तविक
व्यय	अगस्त 2016	अगस्त 2017	फरवरी 2018	फरवरी 2019	फरवरी 2020
राजस्व व्यय (सी)	19,70,224	19,99,005	21,41,772	21,40,612	20,07,399
पूंजीगत व्यय	3,63,999	3,41,000	3,00,441	3,16,623	3,07,714
कुल व्यय (डी)	23,34,223	23,40,005	24,42,213	24,57,235	23,15,113
राजकोषीय घाटा (बी-डी)	(-) 5,67,758	(-) 6,03,651	(-) 6,24,276	(-) 6,34,398	(-) 6,49,418
राजस्व घाटा (ए-सी)	(-) 2,54,259	(-) 3,19,651	(-) 4,16,034	(-) 4,10,930	(-) 4,54,483
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2,56,500	2,25,000	1,95,345	2,00,300	1,91,781
प्रभावी राजस्व घाटा (ई आर डी)	2,241	(-) 94,651	(-) 2,20,689	(-) 2,10,630	(-) 2,62,702
जी डी पी	1,90,66,277	1,88,69,150	1,87,22,302	1,88,40,731	1,89,71,237

4.1 सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के अनुमान

2015-16 के एम टी एफ पी विवरणी में अनुमान लगाया कि 2015-16 की जी डी पी ₹1,41,08,945 करोड़ है और वित्त वर्ष 2016-17 में नाममात्र जीडीपी वृद्धि 12.2 प्रतिशत की दर से और 2017-18 में 12.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। उसी पर आधारित, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जी डी पी लगभग ₹1,77,93,186 करोड़ अनुमानित की गई। 2016-17 की एम टी एफ पी, इस वर्ष की अनुमानित ₹1,50,65,010 करोड़ की जी डी पी पर आधारित थी और 2017-18 में 12.0 प्रतिशत की दर से नाममात्र जी डी पी बढ़ने का अनुमान था। इस गणना पर आधारित 2017-18 के लिए अनुमानित जी डी पी लगभग ₹1,68,72,811 करोड़ थी। 2017-18 के लिए बजट सार के अनुसार इस वर्ष की अनुमानित जी डी पी ₹1,68,47,455 करोड़ थी और 2018-19 के बजट सार में 2017-18 के लिए अनुमानित जी डी पी को संशोधित कर ₹1,67,84,679 करोड़ कर दिया। मई 2020³³ में सी एस ओ द्वारा जारी 2017-18 के जी डी पी आंकड़े ₹1,70,98,304 करोड़ थे।

2018-19 के जी डी पी अनुमानों के मामले में, 2016-17 के एम टी एफ पी में इस वर्ष के लिए अनुमानित जी डी पी ₹1,90,66,277 करोड़ थी। 2017-18 बजट सार में, 2017-18 की जी डी पी का अनुमान ₹1,68,47,455 करोड़ था, और 2018-19 के दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी। तथापि 2018-19 के जी डी पी अनुमानों को एम टी एफ पी 2017-18

³³ वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2019-20

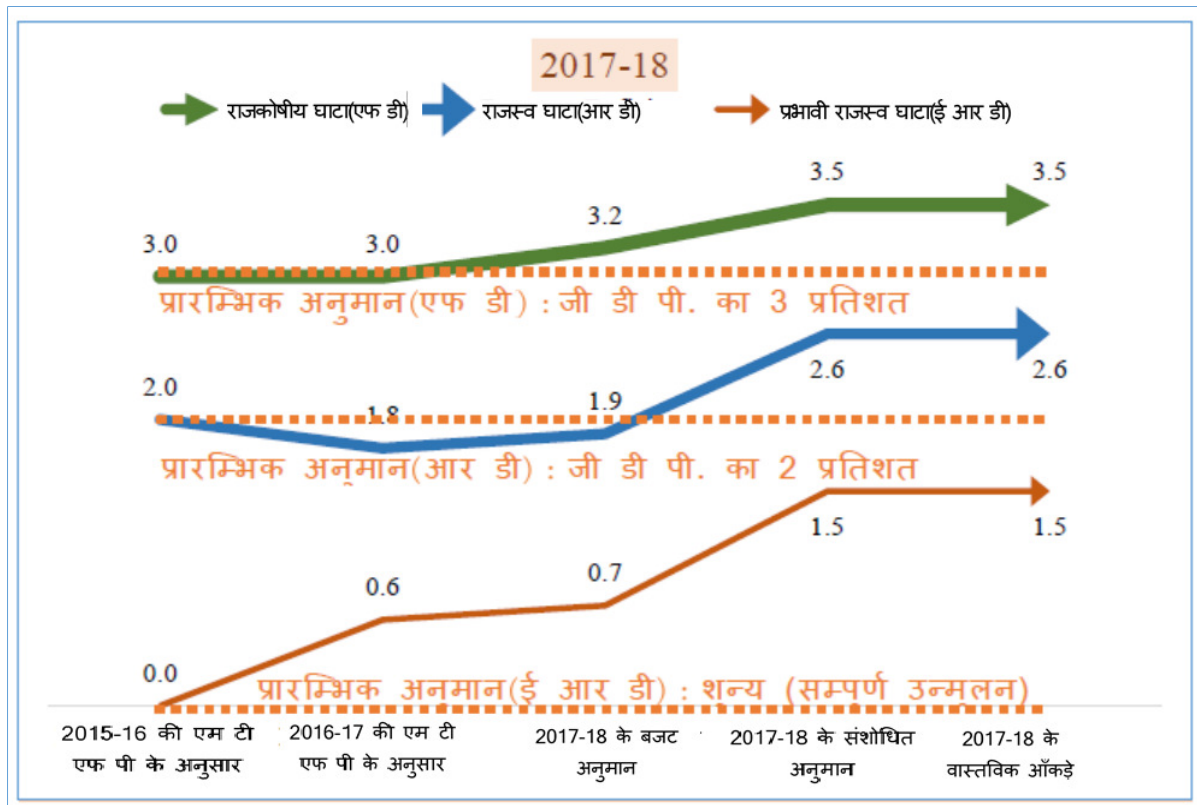
में ₹1,88,69,150 करोड़ रखा गया। 2018-19 के लिए बी ई में, इस वर्ष के लिए जी डी पी को ₹1,87,22,302 करोड़ अनुमानित किया और आर ई में वर्ष के लिए अनुमानित से कुछ बढ़ा कर, ₹1,88,40,731 करोड़ प्रस्तुत किया। 2018-19 के लिए वास्तविक जीडीपी इससे ज्यादा कुछ ₹1,89,71,237 करोड़ था।

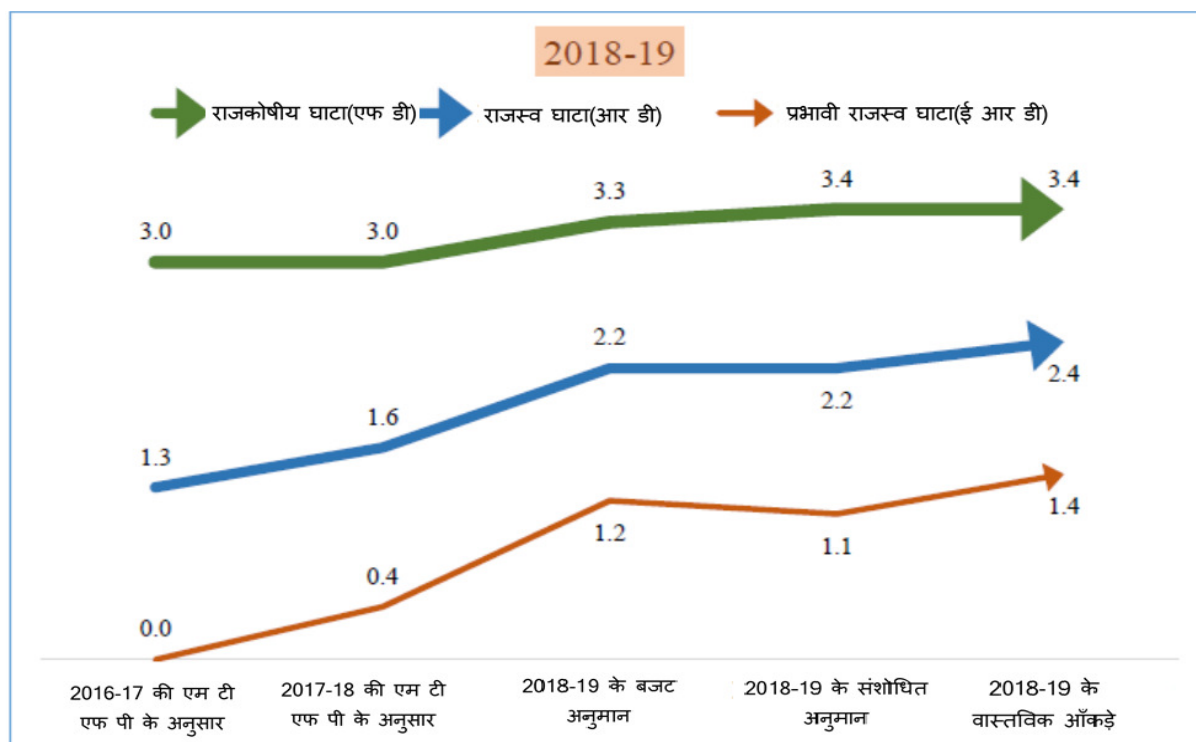
जैसा कि राजकोषीय संकेतक जी डी पी प्रतिशतता के रूप में दर्शाए जाते हैं, कुल जी डी पी के अनुमानों में बदलाव का राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव आता है। यदि जी डी पी के अनुमानों में वृद्धि होती है तो जी डी पी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक कम होंगे भले ही पूर्णांक में घटा बढ़ जाए या इसके विपरीत।

4.2 एफ डी, आर डी और ई आर डी के अनुमानों और वास्तविकों का विश्लेषण

2017-18 और 2018-19 दोनों के लिए तीन प्रमुख एफ आर बी एम संकेतकों के संबंध में एम टी एफ पी अनुमानों और वास्तविकताओं के बीच एक ग्राफिक तुलना, **ग्राफ 4.1** में प्रस्तुत की गई है।

ग्राफ 4.1: 2017-18 और 2018-19 के लिए मध्यम अवधि में एफ डी, आर डी और ई आर डी के अनुमानों से भिन्नता





नोट: आंकड़े जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में संकेतक मूल्य दर्शाते हैं

अनुमानित व वास्तविक राशियों का वर्षवार विश्लेषण नीचे दिया गया है।

2017-18

राजकोषीय घाटा

एम टी एफ पी 2015-16 और 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एफ डी अनुमानों को तीन प्रतिशत पर रखा गया हालांकि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में एफ डी के अनुमान काफी अधिक थे और 3.5 प्रतिशत से 4.1 प्रतिशत तक थे। एम टी एफ पी विवरणियों ने एफ डी के इन उच्च स्तरों को राज्यों को उच्चतर हस्तांतरण (14 वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर) और सामाजिक और कल्याण कार्यक्रमों, अवसंरचना पर उच्च सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता और 7वे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण बताया। हालांकि, विवरणों में निरंतर राजकोषीय समेकन, एफडी की प्रगतिशील कमी और 2017-18 में तीन प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था। ये अनुमान तेल की कीमतों में कमी, विकास पुनरुद्धार विकास योजनाओं के पुनर्निर्धारण और जी एस टी जैसे कर सुधारों के कारण उच्च उत्पाद शुल्क और सब्सिडी पर कम व्यय की अपेक्षाओं पर आधारित थे। 2017-18 के एम टी एफ पी/ 2017-18 बी ई में उच्च सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता के कारण एफ डी में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया क्योंकि निजी निवेश निष्क्रिय था। 2017-18 के लिए एम टी एफ पी 2018-19/ आर ई 2017-18 में एफ डी के अनुमानों को बढ़ाकर

3.5 प्रतिशत कर दिया, जिसे जी एस टी प्रणाली के प्लवन प्रभाव और आर बी आई से कम गैर कर राजस्व वसूली को कारण बताया गया। 2017-18 में वास्तविक एफ डी जी डी पी का 3.5 प्रतिशत था जो कि एम टी एफ पी 2015-16 के प्रारंभिक अनुमानों से काफी अधिक था। इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 के पैरा 2.3 में एफ डी के बी ई, आर ई और वास्तविक के संबंध में भिन्नताओं का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा

एम टी एफ पी 2015-16 में पूर्व के वर्षों में आर डी को सीमित करने में एफ डी के लिए लागू, समान अवरोधों को ही उद्धृत किया और एफ डी लक्ष्यों के प्रति आर डी लक्ष्यों को पुनः संगठित किया। इसके अनुरूप 2017-18 के लिए आर डी को 2 प्रतिशत पर अनुमानित किया। ई आर डी को खत्म करने के लक्ष्य को 2017-18 के लिए आस्थगित कर दिया क्योंकि इसमें केंद्रीय योजनाओं को पुनः तैयार करने की आवश्यकता थी। एम टी एफ पी 2016-17 में 2017-18 के लिए आर डी अनुमान 1.8 प्रतिशत था, जो कि पूर्व के एम एफ वी अनुमानों से 0.2 प्रतिशत कम था, ईआरडी को खत्म करने के लक्ष्य के मुकाबले 0.6 प्रतिशत पर ईआरडी का अनुमान लगाया गया था। आर डी लक्ष्य में कमी का कारण व्यय के पूंजीगत घटक में वृद्धि के लिए नियोजित उपाय थे। ई आर डी उन्मूलन का लक्ष्य इस आधार पर आस्थगित किया गया कि राजस्व व्यय के भीतर असंतुलन को सही करने (यानी पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान पर व्यय और अन्य व्यय के बीच) में अधिक समय लगेगा। एम टी एफ पी 2017-18/ बी ई 2017-18 में आर डी को 2 प्रतिशत अनुमानित किया जोकि एफ आर बी एम लक्ष्य था, लेकिन ई आर डी लक्ष्य में “राजस्व व्यय घटक में संरचनात्मक मुद्दों” के कारण चूक रही इसका अर्थ यह था कि पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय और अन्य व्यय के बीच असंतुलन को अभी भी दूर किया जाना था। एम टी एफ पी 2018-19/ आर ई 2017-18 में हालांकि आर डी और ई आर डी, दोनों में क्रमशः 2.6 प्रतिशत व 1.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि का अनुमान था। इसे व्यय के युक्तिकरण के कारण बताया और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि जी एस टी के रूप में नई कराधान प्रणाली की शुरुआत के संदर्भ में विकास की गतिशीलता वक्र से बहुत अधित नीचे नहीं रहे। आर डी और ई आर डी के लिए वास्तविक, वर्ष की आर ई में अनुमानित उच्च स्तरों पर बने रहे। आर डी और ई आर डी के लिए बी ई, आर ई और वास्तविक के बीच भिन्नता का विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा 2.1 और 2.2 में दिया गया है।

2018-19

राजकोषीय घाटा

एम टी एफ पी 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफ डी अनुमानों को तीन प्रतिशत पर रखा गया जो विकास पुनरुद्धार, व्यय एवं कर सुधारों जैसी अपेक्षाओं पर आधारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के समान ही था। ए टी एफ पी 2017-18 में इस लक्ष्य को बनाए रखा, परंतु ऐसा करने की वजह को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया³⁴। एम टी एफ पी 2018-19/ बी ई 2018-19 के लिए एफ डी में 3.3 प्रतिशत तक की अनुमानित वृद्धि थी जो कि 2017-18 में विचलन, जब वास्तविक एफ डी 3.5 प्रतिशत थी, के बाद राजकोषीय परिमाण के पथ पर वापसी के रूप में देखा गया था। यह उच्च प्राप्तियों और व्यय के युक्तिकरण की अपेक्षाओं पर आधारित था। एम टी एफ पी 2019-20/2018-19 के लिए आर ई में एफ डी के अनुमानों को 3.4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था, लेकिन इसके अलावा यह भी कहा गया कि इससे 31 मार्च 2021 तक जी डी पी के 3 प्रतिशत आस्थगित लक्ष्य के लिए एफ डी की क्रमिक कमी को दर्शाया गया और यह एफ आर बी एम नियमावली, 2004 के नियम 3 के अनुरूप था जिसमें जी डी पी के 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक की एफ डी में वार्षिक कमी की परिकल्पना की गई थी, बड़े हुए लक्ष्य के लिए कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। 2018-19 में एफ डी के लिए वास्तविक आर ई में लक्षित था, यानि जी डी पी का 3.4 प्रतिशत जो कि एम टी एफ पी 2016-17 में दिए गए प्रारंभिक अनुमानों से काफी अधिक था। एफ डी के लिए बी ई, आर ई और वास्तविक के बीच विविधताओं का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** के पैरा 2.3 में दिया गया है।

राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा

एम टी एफ पी और 2016-17 के लिए बजटीय लक्ष्यों की तुलना में पिछले वर्षों में आर डी के संबंध में सुधार को ध्यान में रखते हुए और व्यय के पूंजी घटक को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम को ध्यान में रखते हुए, एम टी एफ पी 2016-17 में 2018-19 के लिए आर डी 1.3 प्रतिशत पर अनुमानित किया जो कि एफ आर बी एम के 2 प्रतिशत लक्ष्य के भीतर था। ई आर डी को खत्म करने के लक्ष्य को पुनः 2018-19 पर आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि राजस्व व्यय के भीतर असंतुलन का सुधार अभी भी चल रहा था। एम टी एफ पी 2017-18 में इंगित किया कि हालांकि आर डी को सीमित करना, एक महत्वपूर्ण मानक है, परंतु पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को अनुदान के राजस्व व्यय के उपयोग और रखरखाव

³⁴ एमटीएफपी 2017-18 का पैरा 21

कार्यों के लिए आर डी को कम करने पर अत्याधिक ध्यान केंद्रित किया जाना लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार आर डी अनुमान वर्ष 2018-19 के लिए 1.6 प्रतिशत था। इसने ई आर डी को 0.4 प्रतिशत अनुमानित किया, लंबित संरचनात्मक मुद्दों के सुलझने तक। एम टी एफ पी 2018-19/2018-19 के लिए बी ई में कहा कि आर डी और ई आर डी के लिए अनुमान केवल जानकारी के लिए थे और यह राजस्व खाते पर घाटे के लक्ष्य को दूर करने के लिए प्रस्तावित किए जा रहे थे। बी ई स्तर पर आर डी के लिए अनुमान 2.2 प्रतिशत था जिसे एम टी एफ पी 2019-20 में आर ई स्तर पर बरकरार रखा गया था। ई आर डी के लिए एम टी एफ पी 2019-20 में कोई अनुमान नहीं दिया गया था, लेकिन यह अनुमान 1.1 प्रतिशत था। बीएजी और खातों से प्राप्त वर्ष के लिए आरडी और ईआरडी के लिए वास्तविक 2.4 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत था। आर डी के लिए बी ई, आर ई और वास्तविक के बीच विविधताओं का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में बाक्स-क में दिया गया है।

उपरोक्त से यह देखा गया कि दोनों वर्षों में सभी तीन सकेतकों के लिए उत्तरोत्तर नीतिगत और बजट दस्तावेजों में उत्तरोत्तर संशोधन किया गया था। इसके अलावा, दोनों वर्षों के लिए बी ई और वास्तविकों के बीच भिन्नताएं थी। परिणामस्वरूप, प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में वास्तविक काफी अधिक थे।

4.3 कर और गैर-कर राजस्व के लिए अनुमान

प्रत्येक वर्ष के एम टी एफ पी विवरण जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व का अनुमान देते हैं। इन अनुमानों की तुलना इस खंड में विश्लेषण किए गए वास्तविक और विविधताओं से की गई है।

4.3.1 कर राजस्व अनुमान

2017-18

एम टी एफ पी एस 2015-16 में अनुमान लगाया था कि कर राजस्व³⁵ 2017-18 में जी डी पी का 6.8 प्रतिशत होगा जो कि ₹12,09,937 करोड़ था। एम टी एफ पी 2016-17 में कर राजस्व के लिए अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित कर 2017-18 में जी डी पी का 7.1 प्रतिशत यानी ₹11,97,970 करोड़ बताया। ऊपर की ओर संशोधन इस धारणा पर आधारित था कि विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए नीतिगत उपायों तथा जी एस टी कार्यान्वयन की वजह से अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि पथ पर लौट आएगी। एम टी एफ पी एस 2017-18 में

³⁵ राज्यों को हस्तांतरण के बाद केंद्र का हिस्सा

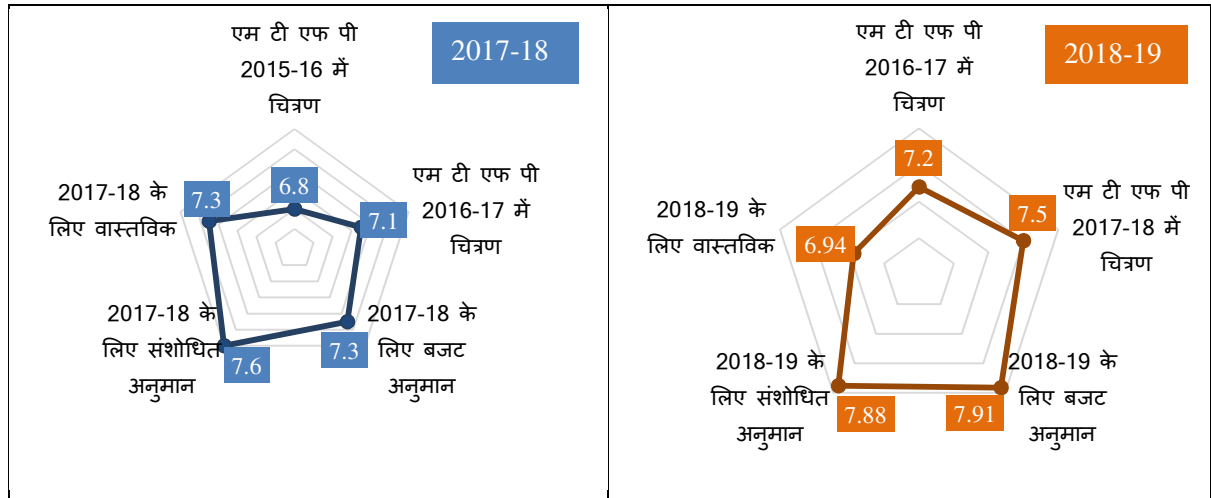
कर राजस्व अनुमानों को 2017-18 के लिए बी ई में ऊपर की ओर संशोधित किया गया जो कि जी डी पी का 7.3 प्रतिशत था। एम टी एफ पी एस 2018-19 में, 2017-18 के लिए संशोधित अनुमानों में, 2017-18 के कर राजस्व संग्रह को ₹61,331 करोड़ के जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर के कारण 7.6 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, जो कि 2017-18 के लिए बी ई में लागू नहीं किया गया था। हालांकि 2017-18 के लिए वास्तविक कर राजस्व, जी डी पी के 7.3 प्रतिशत (ग्राफ 4.2) से कम था। जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 के पैरा 2.1 में उल्लिखित है, बी ई और आर ई के संबंध में वास्तविक कमी में “निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर”, “सी जी एस टी”, “सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क” प्रकरण महत्वपूर्ण थे।

2018-19

एम टी एफ पी एस 2016-17 में उल्लेख है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, सरकार ने अनुमान लगाया था कि विशेष रूप से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए नीतिगत उपाय अल्पावधि में परिणाम दिखाना शुरू कर देंगे। यह भी उम्मीद की गई थी कि कर वृद्धि के लिए अन्य नीतिगत उपायों के साथ जी एस टी के कार्यान्वयन से कर संग्रहण को बढ़ावा मिलेगा। सकल कर राजस्व और राज्यों के हिस्से की गणना के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया था कि 2018-19 में कर राजस्व जी डी पी का 7.2 प्रतिशत होगा जो ₹13,72,772 करोड़ था। एम टी एफ पी एस 2017-18 में कर राजस्व को संशोधित कर 2018-19 के लिए 7.5 प्रतिशत कर दिया जो कि ₹14,15,186 करोड़ रहा। एम टी एफ पी एस 2018-19 में, 2018-19 के बी ई के लिए कर राजस्व जी डी पी का 7.91 प्रतिशत यानी ₹14,80,649 करोड़ थी। एम टी एफ पी एस 2019-20 में, 2018-19 की आर ई में अनुमानित कर राजस्व ₹14,84,406 यानि जी डी पी का 7.88 प्रतिशत कर राजस्व के वास्तविक आंकड़े ₹13,17,211 करोड़. जो जी डी पी का 6.9 प्रतिशत थे। इस प्रकार अनुमानों और की तुलना आंकलन में वास्तविक कर प्राप्ति में एक भारी कमी थी। यह सीजीएसटी, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में अनुमानित संग्रह से कम होने के कारण था।

संकेतकों के अनुमानों के अनुसार कर राजस्व के अनुमानों में भी बार- बार संशोधन और अंत में कमी देखी गई, जिसका राजकोषीय योजना, सार्वजनिक व्यय की योजना और ऋण और उधार लेने की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ग्राफ 4.2: कर राजस्व अनुमान



आकड़े जी डी पी के प्रतिशत के रूप में संकेतक मूल्य दर्शाते हैं

4.3.2 गैर कर राजस्व³⁶ अनुमान

2017-18

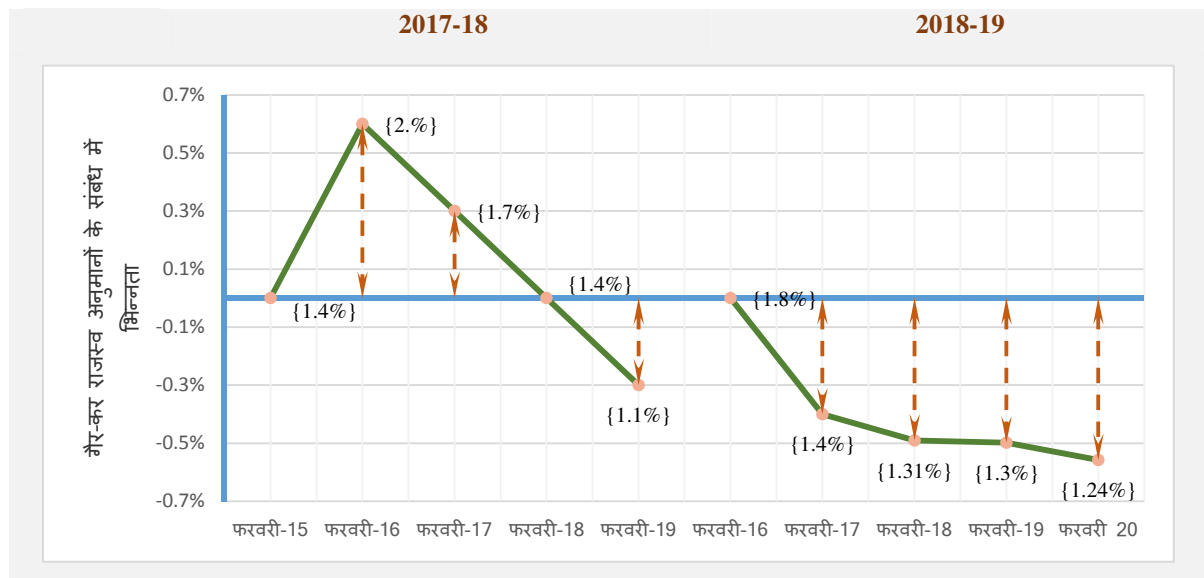
एम टी एफ पी एस 2015-16 में, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सरकार ने गैर कर राजस्व लक्ष्य जी डी पी का 1.4 प्रतिशत तय किया था। एम टी एफ पी विवरण 2016-17 में 2017-18 के लिए एन टी आर अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र के उधमों से लाभांश की दर में वृद्धि और लाइसेंस शुल्क, उगाही और स्पेक्ट्रम नीलामी के कारण दूरसंचार प्राप्तियों में सभावित वृद्धि के कारणों का हवाला देते हुए, 2.0 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए। हालांकि एम टी एफ पी एस 2017-18 में अर्थात् 2017-18 की बी ई में एन टी आर संग्रह अनुमानों को जी डी पी के 1.7 प्रतिशत तक घटा दिया गया था क्योंकि यह माना गया कि 2016-17 के दौरान स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त संग्रह 2017-18 में दोहराया नहीं जा सकता है। एम टी एफ पी एस 2018-19 में आर ई में एन टी आर संग्रह के अनुमानों को 1.4 प्रतिशत तक और घटा दिया गया था, लेकिन कोई विशेष कारण बताया नहीं गया था। हालांकि 2017-18 के लिए वास्तविक जी डी पी का 1.1 प्रतिशत तक कम था (ग्राफ 4.3)। जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 के पैरा 2.1 में उल्लेख किया गया है, आर ई के संबंध में वास्तविक की कमी “लाभांश और लाभ” (₹15,073 करोड़) के तहत महत्वपूर्ण थी मुख्य रूप से आर बी आई से लाभ के हिस्से का अपेक्षा से कम होने, और “आर्थिक सेवाओं से गैर-कर राजस्व” (-31 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

³⁶ एनटीआर प्राप्तियों में विभिन्न स्रोत शामिल होते हैं जैसे लाभांश और लाभ के रूप में संपत्ति पर वापसी, ब्याज, शुल्क, जुर्माना और विविध प्राप्तियां जो सरकारी कार्यों, नियामक शुल्क, लाइसेंस शुल्क और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के अभ्यास में एकत्र की जाती हैं

2018-19

एम टी एफ पी एस 2016-17 में एन टी आर को 2018-19 में जी डी पी का 1.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जो कि ₹3,43,193 करोड़ है। यह 2015-16 के एन टी आर के लिए आर ई में उल्लेखित वृद्धि पर आधारित था। एम टी एफ पी एस 2017-18 में 2018-19 के एन टी आर अनुमानों को कम करते हुए संशोधित कर जी डी पी के 1.4 प्रतिशत अर्थात ₹2,64,168 करोड़ किया गया था। ऐसा 2017-18 के अनुमानों के रूझानों के आधार पर और इन प्राप्ति की प्रकृति के कारण वृद्धि की कम संभावनाएं हैं क्योंकि ये अनम्य हैं और दायरे को विस्तार के लिए उत्तरदायी नहीं है। एम टी एफ पी एस 2018-19 में वर्ष 2018-19 के बीई में 1.3 प्रतिशत या ₹2,45,089 करोड़ का एन टी आर में अनुमान लगाया। एम टी एफ पी एस 2019-20 में, 2018-19 (फरवरी 2019) के लिए आर ई में गैर-कर राजस्व अनुमानों को जी डी पी का 1.3 प्रतिशत अर्थात ₹2,45,276 करोड़ रखा। बी ई और आर ई के बीच भिन्नताओं का विश्लेषण अध्याय 2 के बाक्स-क में दिया गया है। एनटीआर के वास्तविक आंकड़े हालांकि, ₹2,35,705 करोड़ थे जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.24 प्रतिशत था। आरई की तुलना में वास्तविक में कमी "लाभांश और लाभ", "ऊर्जा" और "अन्य सामान्य सेवाओं" के तहत थी। मंत्रालय ने उत्तर (दिसंबर 2020) में कहा कि सरकार ने रेलवे को अपने विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय महत्व प्रदान करते हुए 2017-18 से रेलवे से लाभांश स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है।

ग्राफ 4.3: गैर-कर राजस्व अनुमान



कोष्ठकों '}' में आंकड़े जी डी पी के प्रतिशत के रूप में संकेतक मूल्य दर्शाते हैं

दोनों वर्षों में एन टी आर के प्रारंभिक अनुमान बहुत उत्साहजनक थे और उसके बाद के चरणों में काफी कम हो गए। यह पता चलता है या तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियां अनुमान के लिए आसान नहीं थी या ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के सामान्य प्रदर्शन, स्पेक्ट्रम बिक्री की प्रतिक्रिया, पेट्रोलियम और दूरसंचार आदि जैसे क्षेत्रों के प्रदर्शन के साथ अन्य कारकों पर निर्भर होने के कारण राजस्व का एक स्रोत नहीं है।

4.4 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमान

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में “ऋण और अग्रिमों की वसूली” और अन्य गैर पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं, जो मुख्य रूप से विनिवेश आय से प्राप्तियां हैं। 2017-18 और 2018-19³⁷ के लिए गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए मध्यम अवधि के अनुमानों और वास्तविक का विश्लेषण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:

2017-18

एम टी एफ पी 2015-16 में 2017-18 के लिए ऋण और अग्रिमों की वसूली के प्रारंभिक अनुमान ₹10,500 करोड़ थे, जिसे एम टी एफ पी 2016-17 में बनाए रखा गया। हालांकि 2017-18 के लिए “ऋण और अग्रिम की वसूली” ₹11,932 करोड़ थी जो बी ई अनुमान से अधिक थी। आर ई में महत्वपूर्ण (46 प्रतिशत) वृद्धि अनुमान में ₹17,473 करोड़ था। “ऋण और अग्रिमों की वसूली” के लिए की गई वास्तविक आंकड़े आर ई से 10.5 प्रतिशत कम रहे यानी ₹15,633 करोड़।

“अन्य गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां” जो कि विनिवेश से मुख्य प्राप्तियां हैं, को 2017-18 के लिए एम टी एफ पी 2015-16 में ₹50,000 करोड़ पर अनुमानित किया था। एम टी एफ पी 2016-17 में इसमें नीचे की ओर ₹40,000 करोड़ तक संशोधित किया गया। 2017-18 के बी ई में इस आधार पर अनुमान उच्चतर स्तर ₹72,500 करोड़ तक अनुमानित किया गया। इस वृद्धि का श्रेय रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने/बिक्री के लिए “सक्रिय उपायों” और विनिवेश के लिए बढ़ी हुई गति को दिया गया। इस शीर्ष के तहत अनुमान आगे के लिए बढ़ाया गया था और आर ई स्तर पर ₹1,00,000 करोड़ तक किया लेकिन एम आर एफ पी एस 2018-19 में कोई कारण नहीं बताए गए। अन्य गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वास्तविक आर ई के साथ ₹1,00,045 करोड़ पर बरकरार रहें थे। 2017-18 के दौरान यह देखा गया, एच पी सी एल- ओ एन जी सी सौदा से (₹36,915 करोड़), जी आई सी और न्यू इंडिया

³⁷ व्यक्तिगत लेनदेन से विनिवेश आय पर डेटा दीपम (निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन) विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है।

एशयोरेंस के आईपीओ (₹17,357 करोड़), एनटीपीसी के ऑफर फॉर सेल्स (ओएफएस) (₹9,117 करोड़) और ईटीएफ (₹14,500 करोड़) से महत्वपूर्ण संग्रह हुआ था।

2018-19

एम टी एफ पी 2016-17 में 2018-19 के लिए ऋण और अग्रिमों की वसूली के प्रारंभिक अनुमान ₹10,500 करोड़ था जिसे एम टी एफ पी 2017-18 में कम कर ₹10,000 करोड़ कर दिया। बी ई में इस शीर्ष के तहत अनुमान ₹12,199 करोड़ था जबकि आर ई में इसे 8 प्रतिशत, अर्थात् ₹13,155 करोड़ तक अधिक होने की उम्मीद की गई थी। 2018-19 के लिए ऋण और अग्रिमों की वसूली के वास्तविक आंकड़े ₹18,052 करोड़ थे जो कि आर ई से 37 प्रतिशत अधिक थे।

एम टी एफ पी 2016-17 में 2018-19 के लिए अन्य गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹40,000 करोड़ पर अनुमानित की गईं। हालांकि एम टी एफ पी 2017-18 में इन्हें ऊपर की ओर संशोधित कर ₹47,000 करोड़ किया। परंतु ये अनुमान 2017-18 की बी ई से तुलना करने पर बहुत अपरिवर्तनवादी थे। 2018-19 की बी ई में अन्य गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के तहत संग्रह के लिए अनुमान ₹ 80,000 करोड़ तक बढ़ाए गए थे, लेकिन 2017-18 के लिए आर ई की तुलना में बहुत कम था इस उम्मीद पर कि प्रोद्वन कम हो जायेगा क्योंकि विनिवेश के लिए पात्र कंपनियों की संख्या कम हो जाएगी। यह अनुमान आर ई स्तर पर अपरिवर्तित रहे। अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़े ₹94,727 करोड़ थे जो कि बी ई/आर ई से लगभग 18 प्रतिशत अधिक थे। बी ई /आर ई से भिन्नता राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण (₹9,682 करोड़) से प्राप्तियों के कारण थी, जिनकी परिकल्पना नहीं की गई थी। ई टी एफ से महत्वपूर्ण प्राप्तियां (₹45,079 करोड़³⁸), आर ई सी का रणनीतिक विनिवेश (₹14,500 करोड़) और एक्सिस बैंक में एस यू यू टी आई होल्डिंग की बिक्री (₹5,378 करोड़) से थी।

इस प्रकार दोनों वर्षों में देखा गया कि सरकार को विनिवेश के माध्यम से संसाधन जुटाने को, इन वर्षों में एफडी को नियंत्रित करने के लिए शुरू के अनुमान से कहीं अधिक उच्च स्तर तक बढ़ाना पड़ा।

4.5 मध्यम अवधि व्यय ढांचे विवरण में अनुमान

2017-18

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए व्यय के मदों का अनुमान सबसे पहले एम टी ई एफ विवरण 2015-16 (अगस्त 2015) में दर्शाया गया। 2015-16 में प्रचलित बृहत-आर्थिक मापदंडों पर

³⁸ इसमें ₹7,047 करोड़ के ईटीएफ के हिस्से के रूप में बेची गई एसयूटीआई होल्डिंग्स से प्राप्त आय भी शामिल है।

आधारित ये अनुमान 2016-17 के एम टी ई एफ विवरण (अगस्त 2016) में संशोधित कर प्रस्तुत किए गए। इसके बाद, वित्त वर्ष 2017-18 के बी ई और आर ई पर आधारित व्यय अनुमानों को क्रमशः 2017-18 के एम टी ई एफ विवरण (अगस्त 2017) और एम टी एफ पी विवरण 2018-19 (अगस्त 2018) में प्रस्तुत किया गया। इन व्यय मदों के लिए 2017-18 के वास्तविक 2019-20 के बजट सार (फरवरी 2019) में प्रस्तुत किए गए थे।

2018-19

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यय अनुमान पहली बार एम टी ई एफ विवरण 2016-17 (अगस्त 2016) में दिखाई दिए। ये 2017-18 के मामले में थे, एम टी ई एफ 2017-18 (अगस्त 2017) के विवरण के अनुसार प्रासंगिक वर्ष के दौरान प्रचलित मैक्रो-इकोनॉमिक मापदंडों के आधार पर संशोधित/अद्यतन; 2018 19 का एम टी ई एफ स्टेटमेंट (अगस्त 2018) जिसने 2018-19 के लिए बीई और 2019 20 का बी ए जी स्टेटमेंट (फरवरी 2019) दिया जिसमें 2018 19 के लिए आरई के आंकड़े शामिल हैं। 2018-19 के लिए व्यय के मदों के संदर्भ में वास्तविक, बजट सार 2020-21 (फरवरी 2020) में प्रस्तुत किए गए थे। 2019-20 का एम टी एफ पी विवरण जो 2019 में देय था, तैयार नहीं किया गया है और संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4.5.1 पूंजीगत और राजस्व व्यय के अनुमान

2017-18 और 2018-19 के लिए विभिन्न एम टी ई एफ विवरणों और वास्तविकों में राजस्व और पूंजीगत व्यय के अनुमानों का ब्यौरा नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है। 2017-18 और 2018-19 के लिए व्यय अनुमानों का शीर्षवार विवरण और दो वर्षों के लिए वास्तविक अनुलग्नक 4.1 में दिए गए हैं।

तालिका 4.2: पूंजीगत और राजस्व व्यय के अनुमान
2017-18 के लिए अनुमान

व्यय के शीर्ष	वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए अनुमान (वि.व. 2015-16 के एम टी ई एफ विवरण में)	वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए अनुमान (वि.व. 2016-17 के एम टी ई एफ विवरण में)	एम टी ई एफ 2017-18 में बी ई	वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए 2017-18 के एम टी ई एफ में आर ई	वित्त वर्ष 2018-19 के एम टी ई एफ विवरण अंतिम वास्तविक	प्रारंभिक अनुमानों के संबंध में वास्तविक में प्रतिशत अंतर
	अगस्त-15	अगस्त-16	अगस्त-17	अगस्त-18	अगस्त-18	
कुल राजस्व व्यय	17,79,614	18,28,916	18,36,933	19,44,305	18,78,964	6%
कुल पूंजीगत व्यय	2,84,541	2,68,865	3,09,802	2,73,444	2,63,702	-7%
कुल व्यय	20,64,155	20,97,781	21,46,735	22,17,749	21,42,666	4%

2018-19 के लिए अनुमान

	अगस्त-16	अगस्त-17	अगस्त-18	फरवरी-19 ³⁹	फरवरी-20	
कुल राजस्व व्यय	19,70,224	19,99,005	21,41,772	21,40,612	20,07,399	1.85%
कुल पूंजीगत व्यय	3,63,999	3,41,000	3,00,441	3,16,623	3,07,714	-15%
कुल व्यय	23,34,223	23,40,005	24,42,213	24,57,235	23,15,113	-0.83%

2017-18

एम टी ई एफ विवरणियों से वित्तीय वर्ष 2017-18 के व्यय के आंकलनो, अनुमानों और अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि शुरुआती अनुमानों से राजस्व व्यय में छः प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में लगभग सात प्रतिशत की कमी आई। कुल मिलाकर शुरुआती अनुमानों से कुल व्यय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। शीर्ष वार ब्यौरे की जांच से पता चलता है कि राजस्व व्यय के मामले में, शीर्ष जहां अनुमानों की तुलना में व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, वे थे वेतन (17 प्रतिशत), पेंशन (29 प्रतिशत), डाक (81 प्रतिशत), कर प्रशासन (1343 प्रतिशत), स्वास्थ्य (38 प्रतिशत), समाज कल्याण (26 प्रतिशत), कृषि आदि (85 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (50 प्रतिशत), ऊर्जा (148 प्रतिशत) और आई टी/टेलीकोम (55 प्रतिशत)। वहीं दूसरी ओर अनुमानों में महत्वपूर्ण कमी, उर्वरक सब्सिडी (17 प्रतिशत), खाद्य सब्सिडी (29 प्रतिशत), पेट्रोलियम सब्सिडी (28 प्रतिशत), वित्त (84 प्रतिशत) और परिवहन (11 प्रतिशत) में इंगित की गई। पूंजीगत व्यय के प्रकरण में, अनुमानों की तुलना में वास्तविक में उल्लेखनीय वृद्धि स्वास्थ्य (153 प्रतिशत), ऊर्जा (19 प्रतिशत) और आई टी/टेलीकोम (27 प्रतिशत) था। प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में वास्तविक में महत्वपूर्ण कमी रक्षा (19 प्रतिशत), वित्त (24 प्रतिशत) वाणिज्य और उद्योग (47 प्रतिशत) तथा राज्यों को ऋण (65 प्रतिशत) में था।

2018-19

2018-19 के लिए इसी तरह की जांच में सामने आया कि राजस्व व्यय के प्रकरण में, प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में लगभग 1.85 प्रतिशत की वृद्धि थी और पूंजीगत व्यय के प्रकरण में, प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में वास्तविकों में 15 प्रतिशत की कमी थी। कुल मिलाकर, प्रारंभिक अनुमानों से कुल व्यय में 0.83 प्रतिशत की कमी थी। हालांकि, 2019-20 के एमटीईएफ विवरण के अभाव में, विविधताओं का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

³⁹ बीएजी 2019-20 के आंकड़ों। एमटीईएफ के रूप में 2019-20 के लिए 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों तैयार नहीं किए गए थे

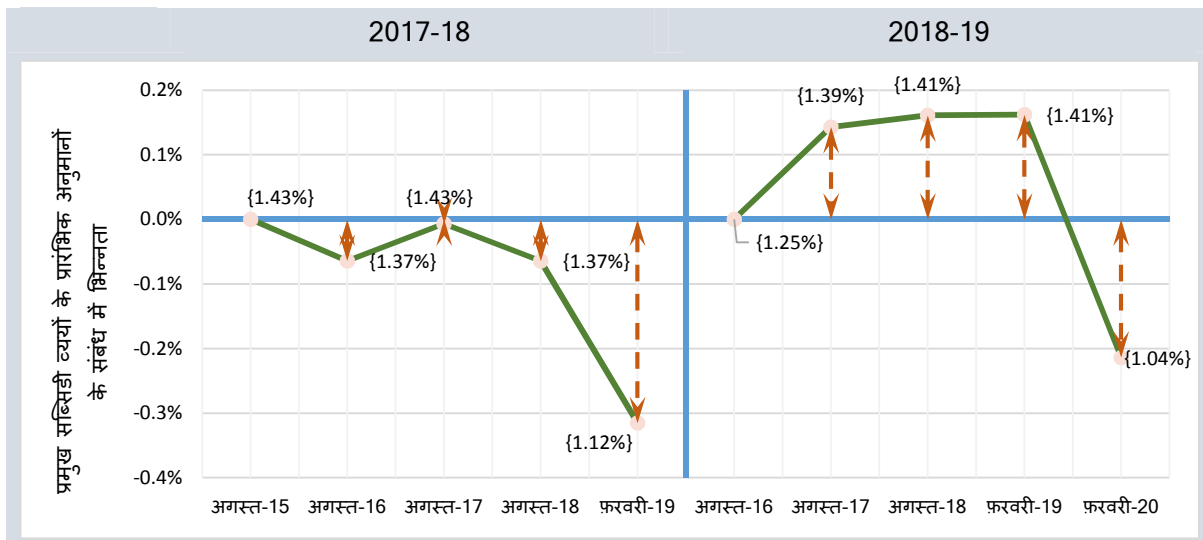
4.5.2 प्रमुख सब्सिडियों के अनुमान

वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मुख्य सब्सिडियों पर व्यय के संबंध में एम टी ई एफ विवरणियों और वास्तविकों के अनुमानों को तालिका 4.3 में दिया गया है और ग्राफ 4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3 प्रमुख सब्सिडियों के आंकलन/अनुमान और वास्तविक

	वित्त वर्ष 17-18 के पूर्वानुमान (वित्त वर्ष 2015-16 के एम टी ई एफ विवरण में)	वित्त वर्ष 17-18 के पूर्वानुमान (वित्त वर्ष 2016-17 के एम टी ई एफ विवरण में)	एम टी ई एफ बी ई 2017-18 में	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एम टी ई एफ में 2017-18 की आर ई	वास्तविक (वित्त वर्ष 2018-19 के एम टी ई एफ विवरण)
2017-18 के लिए आंकलन/ अनुमान और वास्तविक					
	अगस्त-2015	अगस्त-2016	अगस्त-2017	अगस्त-2018	अगस्त-2019
उर्वकर सब्सिडी	80,000	70,000	70,000	65,000	66,441
खाद्य सब्सिडी	1,41,000	1,40,000	1,45,339	1,40,282	1,00,316
पेट्रोलियम सब्सिडी	34,000	21,000	25,000	24,460	24,352
कुल मुख्य सब्सिडियां	2,55,000	2,31,000	2,40,339	2,29,742	1,91,109
कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	14.3%	12.6%	13.1%	11.8%	10.2%
2018-19 के लिए आंकलन/ अनुमान और वास्तविक					
	अगस्त-2016	अगस्त-2016	अगस्त-2018	फरवरी-2019	फरवरी-2020
उर्वकर सब्सिडी	72,000	70,000	70,090	70,086	70,605
खाद्य सब्सिडी	1,45,000	1,75,000	1,69,323	1,71,298	1,01,327
पेट्रोलियम सब्सिडी	21,500	18,000	24,933	24,833	24,837
कुल मुख्य सब्सिडियां	2,38,500	2,63,000	2,64,346	2,66,217	1,96,769
कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	12.1%	13.2%	12.3%	12.4%	9.8%

ग्राफ 4.4: प्रमुख सब्सिडियों के प्रारंभिक अनुमानों के संबंध में भिन्नताएं



कोष्ठकों '{ }' में आंकड़े जी डी पी के प्रतिशत के रूप में संकेतक मूल्य दर्शाते हैं

दो वर्षों के संबंध में स्थिति का नीचे विश्लेषण दिया गया है

2017-18

उपरोक्त तालिका 4.3 से, यह देखा जा सकता है कि एम टी ई एफ 2015-16 में 2017-18 के लिए उर्वरक सब्सिडी पर अनुमान व्यय ₹80,000 करोड़ था। इसे एम टी ई एफ 2016-17 में ₹70,000 करोड़ तक कम किया (12.5 प्रतिशत की गिरावट) और 2017-18 की बी ई में इसी स्तर पर बनाए रखा। हालांकि, आर ई स्तर पर/एम टी ई एफ 2018-19 में, उर्वरक सब्सिडी के लिए अनुमानों को ₹65,000 करोड़ तक कम किया (7 प्रतिशत कटौती)। 2017-18 के दौरान उर्वरक सब्सिडी पर वास्तविक व्यय मामूली बढ़ कर ₹66,441 करोड़ था। 2017-18 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी का अनुमान एम टी ई एफ 2015-16 में ₹34,000 करोड़ थे जिसे एम टी ई एफ 2016-17 में ₹21,000 करोड़ (लगभग 38 प्रतिशत की गिरावट) तक कम किया, 2017-18 के लिए बी ई में ₹25,000 करोड़ (19 प्रतिशत बढ़ोतरी) तक बढ़ाया और एम टी ई एफ 2018-19 में आर ई में मामूली रूप से, ₹24,460 करोड़ (2 प्रतिशत गिरावट) तक कम किया और वास्तविक, आर ई के समान ही ₹24,352 करोड़ थे। खाद्य सब्सिडी के प्रकरण में, हालांकि पूर्वानुमान और अनुमानों ₹1,40,000 करोड़ (एम टी ई एफ 2016-17) और ₹1,45,339 करोड़ (बी ई 2017-18) के बीच में थे, वास्तविक आकड़ें ₹1,00,316 करोड़ पर, आरई से 28 प्रतिशत कम थे। समग्र रूप से, 2017-18 के दौरान मुख्य सब्सिडीयों पर वास्तविक व्यय अगस्त 2016 के प्रारंभिक अनुमानों से 17 प्रतिशत कम था और इन सब्सिडीयों के लिए आर ई से 26 प्रतिशत कम था।

2018-19

प्रमुख सब्सिडीयों के लिए 2018-19 वर्षों के अनुमानों और वास्तविकों के संबंध में स्थिति को भी उपरोक्त तालिका 4.3 में दिया गया है। उर्वरक सब्सिडी के प्रकरण में वास्तविक व्यय ₹70,605 करोड़ था जो कि विभिन्न स्तरों पर अनुमानित ₹70,000 करोड़ से ₹72,000 करोड़ के बीच था। अगस्त 2016 में 2018-19 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी अनुमान ₹21,500 करोड़ था। इसे अगस्त 2017 में ₹18,000 करोड़ यानी 16 प्रतिशत तक घटा दिया गया। हालांकि, 2018-19 के बी ई में, पेट्रोलियम सब्सिडी अनुमानों को ₹24,933 करोड़ (39 प्रतिशत वृद्धि) तक बढ़ा दिया गया। आर ई और वास्तविक काफी हद तक बी ई के अनुरूप थे। खाद्य सब्सिडी के प्रकरण में, प्रारंभिक अनुमानों, बजट संशोधित अनुमानों और वास्तविक के बीच तेज उतार-चढ़ाव देखे गए थे। अगस्त 2016 में खाद्य सब्सिडी के अनुमान जो ₹1,45,000 करोड़ थे, को अगस्त 2017 में ₹1,75,000 (30 प्रतिशत की वृद्धि) बढ़ा दिया था। अनुमानों को बी ई

(₹1,69,323 करोड़) और आर ई सत्र (₹1,71,298 करोड़) पर कम किया गया। हालांकि इन की तुलना में वास्तविक ₹1,01,327 करोड़ पर काफी कम थे। खाद्य सब्सिडी के वास्तविक आंकड़े बी ई और आर ई से लगभग 41 प्रतिशत कम थे। कुल मिलाकर **तालिका 4.3** में दी गई प्रमुख सब्सिडियों पर 2018-19 के लिए वास्तविक व्यय अगस्त 2016 के प्रारंभिक अनुमानों से 17 प्रतिशत कम और आरई की तुलना में 26 प्रतिशत कम था।

इस प्रकार, प्रमुख सब्सिडियों के प्रकरण में, अनुमानों की तुलना में वास्तविकों में पूर्णांकों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, दोनों तरह से कटौती देखी गई। हालांकि, इन कटौती को खाद्य सब्सिडी के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त बजटीय संसाधनों और उर्वरक कंपनियों और ओएमसी को क्रमशः उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी की प्रतिपूर्ति में बढ़ते बकाया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसका प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में विस्तार से वर्णन किया गया है। खाद्य सब्सिडी पर राजस्व व्यय को रोकने के लिए एन एस एस एफ के माध्यम से बजटेंतर प्रबंधनों का उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण है और इसका प्रतिवेदन के **अध्याय 2** में विस्तार से वर्णन किया गया है।

4.6 घाटे के वित्तपोषण के लिए उधार

एम टी एफ पी विवरणियां, कर और गैर-कर राजस्व के लिए अनुमान प्रदान करती हैं और एम टी ई एफ विवरणी राजस्व और पूंजीगत व्यय के अनुमान प्रस्तुत करती हैं। प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर अर्थात् राजकोषीय घाटे, को उधारी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। किसी वर्ष के लिए अनुमानित उधारियों की गणना, उस वर्ष के एम टी एफ पी विवरणियों में दिए कर, गैर-कर राजस्व, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और एम टी ई एफ विवरणियों में दिए राजस्व और पूंजीगत व्यय के अनुमानों पर आधारित होती है। ये एफ डी के अनुमानों के साथ मेल रखते हैं।

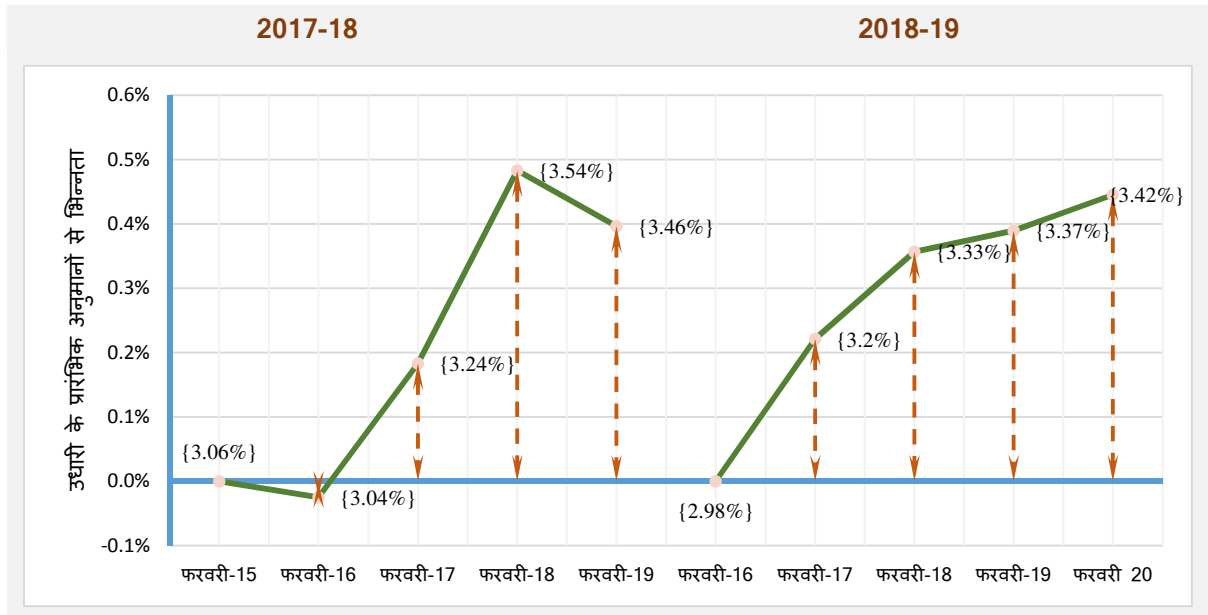
2017-18

एम टी एफ पी एस 2015-16 में, सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए उधारियों को जी डी पी के 3.06 प्रतिशत अनुमान किया था। एम टी एफ पी एस 2016-17 में इस अनुमान को जी डी पी के 3.04 प्रतिशत तक संशोधित किया। बाद में, एम टी एफ पी एस 2017-18 वर्ष के बी ई पर आधारित, 2017-18 के लिए उधारी अनुमान को जी डी पी के 3.24 प्रतिशत तक संशोधित किया जिसे एम टी एफ पी एस 2018-19 में 2017-18 के लिए आर ई में, और भी 3.54 प्रतिशत तक बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत दिया गया। हालांकि, 2017-18 के लिए वास्तविक उधारियां जी डी पी के 3.46 प्रतिशत तक कम बनी रहीं (**ग्राफ 4.5**)।

2018-19

एम टी एफ पी एस 2016-17 में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उधारियों को जी डी पी का 2.98 प्रतिशत अनुमानित किया। एम टी एफ पी एस 2017-18 में इस अनुमान को 2018-19 के लिए जी डी पी के 3.2 प्रतिशत पर संशोधित किया। इसके बाद, 2018-19 के बी ई पर आधारित एम टी एफ पी एस 2018-19 में 2018-19 के लिए संशोधित उधारी अनुमान को जी डी पी के 3.33 प्रतिशत तक बढ़ाया। इसे पुनः एम टी एफ पी विवरणी 2019-20 में 2018-19 के लिए आर ई में 3.37 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक उधारियां और भी अधिक, जी डी पी के 3.42 प्रतिशत पर बनी रही। (ग्राफ 4.5)

ग्राफ 4.5: उधारी अनुमान



कोष्ठकों '{ }' में आंकड़े, जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में सांकेतिक मूल्य दर्शाते हैं।

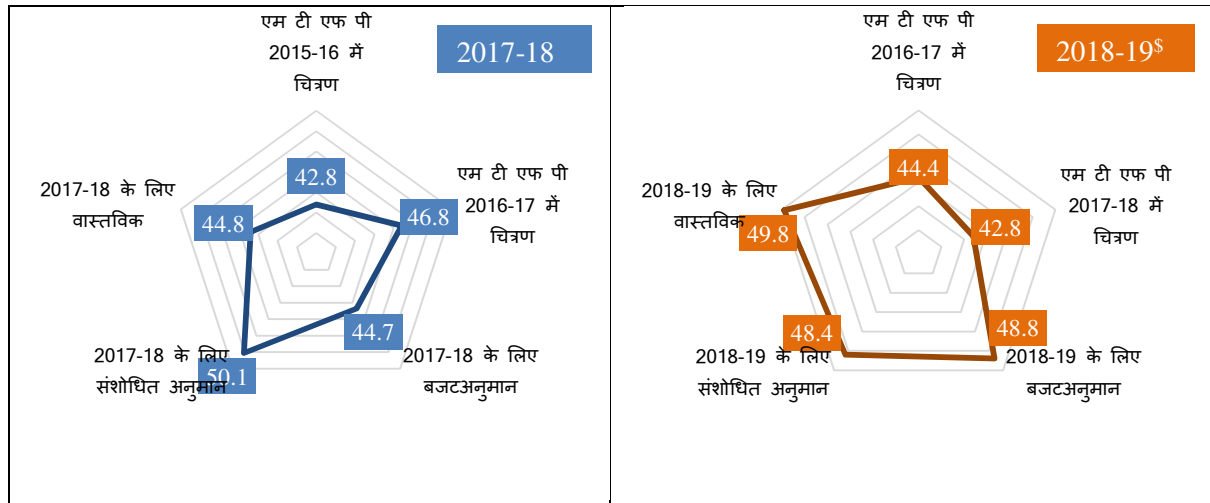
उपरोक्त विश्लेषण में बताई गई उधारियां, केवल वे उधारियां हैं, जिन्हें सरकार के खातों में लेखांकित किया गया है। इनमें राजस्व और पूंजीगत व्यय के लिए सरकार की ओर से किए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए उधार शामिल नहीं है, जिसका वर्णन अध्याय 2 में किया गया है।

4.7 कुल बकाया देयता/ केन्द्र सरकार ऋण अनुमान

कुल बकाया देयता/केन्द्र सरकार के ऋण की पुरानी और नई दोनों परिभाषाओं को सम्मिलित करते हुए कुल बकाया देयता और केन्द्र सरकार के ऋण, इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में विस्तार से दिए गए हैं। इस खंड में नीतिगत विवरण में वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए

कुल बकाया देयता/ केन्द्र सरकार के ऋण के अनुमानों और वास्तविकों का विश्लेषण किया गया है।

ग्राफ 4.6: कुल बकाया देयता/केन्द्र सरकार के ऋण अनुमान



[§] एम टी एफ पी 2019-20 और एम टी एफ पी 2020-21 के आंकड़ों में शब्द, 'केन्द्र सरकार के ऋण', नई परिभाषा के अनुसार है।

आंकड़े जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में संकेतक मूल्य दर्शाते हैं।

2017-18

एम टी एफ पी एस 2015-16 में, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल देयताएं जी डी पी के 42.8 प्रतिशत पर अनुमानित की गईं। यह इस अपेक्षा पर आधारित था कि राजकोषीय समेकन से लाभ होगा और एफ डी को रोका जा सकेगा जिससे सरकारी उधारी में कमी आएगी। हालांकि एम टी एफ पी एस 2016-17 में देयताओं के अनुमानों को जी डी पी के 46.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। यद्यपि यह वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में अनुमानित जी डी पी के 47.1 प्रतिशत से कम था, इस अपेक्षा पर कि मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए आरबीआई नीतिगत उपाय जल्द ही परिणाम दिखाने शुरू कर देंगे। एम टी एफ पी एस 2017-18 में, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जी डी पी अनुमान से कुल देनदारियों के लिए अनुमानों को एनएसएसएफ से निवेश के संबंध में परिवर्तनों के अपेक्षित प्रभाव के आधार पर, 44.7 प्रतिशत तक नीचे की ओर संशोधित किया था। एम टी एफ पी एस 2018-19 में, 2017-18 के लिए कुल बकाया देयताओं के आर ई को जी डी पी के 50.1 प्रतिशत पर संशोधित कर बढ़ाया। यह राजकोषीय समेकन के बावजूद, कम नाममात्र जी डी पी विकास संख्या के कारण था। कुल वास्तविक देयताएं जी डी पी का 44.8 प्रतिशत था जोकि अनुमानों से काफी कम था। ऐसा उच्च नाममात्र जी डी पी और कम वास्तविक उधार के कारण था।

2018-19

एम टी एफ पी एस 2016-17 में, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल देयताएं जी डी पी की 44.4 प्रतिशत अनुमानित की गई। यह वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में अनुमानित जी डी पी के 47.1 प्रतिशत से कम था। 2018-19 के लिए अनुमान इस धारणा पर आधारित थे कि राजकोषीय समेकन से लाभ मिलने शुरू हो गए और घाटे को रोका जा रहा था। एम टी एफ पी एस 2017-18 में, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल देयताओं को पुनः संशोधित कर 42.8 प्रतिशत तक कम कर दिया, यह समेकन की गति के सही राह पर चलने के अनुमान पर आधारित था। हालांकि केन्द्र सरकार के ऋण की विस्तृत परिभाषा जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा जुटाए ई बी आर जिसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा सेवित किया जाएगा, सम्मिलित था, का हवाला देते हुए, एम टी एफ पी एस 2018-19 में, इस वर्ष के लिए बी ई के स्तर पर, 2018-19 की बकाया देयताओं का अनुमान जीडीपी के 48.8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया था। एम टी एफ पी एस 2019-20 में, 2018-19 के लिए आर ई में, स्थिर मुद्रस्फीति की वजह से उधारी की ब्याज कीमत में कमी और फिर ऋण स्टॉक की वृद्धि, के आधार पर कुल देयता अनुमानों को जी डी पी के 48.4 प्रतिशत पर संशोधित किया था। एम टी एफ पी एस 2020-21 के अनुसार 2018-19 के लिए केन्द्र सरकार वास्तविक⁴⁰ ऋण, जी डी पी के 48.7 प्रतिशत था।

इस संदर्भ में यह इंगित किया कि लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों और कुछ अपवर्जित देनदारियों को ध्यान में रखते हुए **अध्याय 3** में 2017-18 और 2018-19 दोनों के लिए जीडीपी के लिए कुल देयता के अनुपात की गणना की है। उसी के आधार पर, कुल देयता/केन्द्र सरकार ऋण का जी डी पी से अनुपात, बजट दस्तावेजों में दिए गए, अनुपात से अधिक होगा।

4.8 लेखापरीक्षा सारांश

विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्तियों और व्यय के लिए नीति और बजट दस्तावेजों में किए गए अनुमान और तीन वित्तीय संकेतकों और वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों पर किए गए तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि सभी तत्व और घटक के संबंध में प्रत्येक वर्ष अनुमान में लगातार संशोधन किया गया है। हालांकि, अनुमान में बार-बार संशोधन के बावजूद, वास्तविक आंकड़ों से अनुमान भिन्न थे जिन्होंने एफ आर बी एम अधिनियम में

³⁹ “अंतिम वास्तविक” के तौर पर माना क्योंकि 2020-21 के बजट दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के समय पर, सी ए जी द्वारा 2018-19 के लेखों को प्रमाणित करना बाकी था।

परिकल्पित उद्देश्य जो कि मध्यम अवधि के ढांचे में राजकोषीय संचालन के प्रबंधन है, उसे कमजोर कर दिया।